2019:CGHC:24455

AFR

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

विविध अपील (सी) संख्या 672/2015

फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड , शाखा प्रबंधक के माध्यम से, शाखा कार्यालय शॉप नंबर 3, द्वितीय तल, मारुति बिजनेस पार्क, राजकुमार कॉलेज के पास, रायपुर, थाना सरस्वती नगर, सिविल एवं राजस्व जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ (बीमाकर्ता)।

---- **अपीलकर्ता**

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. सुश्री आरती सिंह ठाकुर खंगार, पति स्वर्गीय उमेश सिंह ठाकुर खंगार, आयु लगभग 24 वर्ष, पेशा गृहिणी, निवासी केलकर पारा, भीमसेन किराना शॉप के पास, स्टेशन रोड, थाना गंज, सिविल एवं राजस्व जिला रायपुर, छत्तीसगढ़(दावेदार)।

2. राजेश्वर सिंह राजपूत, पिता रामस्वरूप राजपूत, इंद्रापारा बाजार, तिल्दा-नेवरा, थाना नेवरा, तहसील एवं जिला बालोदाबाजार, सिविल एवं राजस्व जिला बालोदाबाजार, छत्तीसगढ़ (मालिक)।

---- **प्रतिवादीगण**

अपीलकर्ता के लिए:श्री रोहिताश्व सिंह, अधिवक्ता।
प्रतिवादी संख्या 1 के लिए:श्री ए. एल. सिंगरौल, अधिवक्ता।
प्रतिवादी संख्या 2 के लिए: कोई नहीं, यद्यपि सूचना प्रेषित किया गया है।

और

विविध अपील (सी) संख्या 369/2016

सुश्री आरती सिंह ठाकुर खंगार, पति स्वर्गीय उमेश सिंह ठाकुर खंगार, आयु लगभग 24 वर्ष, पेशा गृहिणी, निवासी ग्राम केलकरपारा, भीमसेन ग्रासोरी शॉप के पास, स्टेशन रोड, रायपुर, तहसील एवं जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ (दावेदार)।

---- **अपीलकर्ता**

बनाम

1. राजेश्वर सिंह खंगार, पिता रामस्वरूप राजपूत, निवासी इंद्रापारा बाजार, तिल्दा-नेवरा, थाना नेवरा, तहसील एवं जिला बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़ (चालक)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, शाखा प्रबंधक के माध्यम से, शाखा कार्यालय शॉप नंबर 3, द्वितीय तल, मारुति बिजनेस पार्क, राजकुमार कॉलेज के पास, रायपुर, छत्तीसगढ़ (बीमाकर्ता)।

---- **प्रतिवादी**

अपीलकर्ता के लिए:श्री ए. एल. सिंगरौल, अधिवक्ता।
प्रतिवादी संख्या 1 के लिए:कोई नहीं, यद्यपि सूचना प्रेषित किया गया है।
प्रतिवादी संख्या 2 के लिए:श्री रोहिताश्व सिंह, अधिवक्ता।

माननीय श्री न्यायमूर्ति संजय अग्रवाल

बोर्ड पर अवार्ड

03.09.2019

1. ये दोनों विविध अपीलें छत्तीसगढ़, रायपुर के मुख्य मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल (संक्षेप में 'दावा ट्रिब्यूनल') द्वारा दावा केस संख्या 57/2012 में 30.03.2015 को पारित एक सामान्य अवार्ड से उत्पन्न हुई हैं, जिसमें दावा ट्रिब्यूनल ने दावे को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कुल मुआवजे की राशि 3,62,600/- रुपये दावा याचिका दाखिल करने की तारीख से इसके वसूली तक 6% वार्षिक ब्याज के साथ दी, जबकि बीमा कंपनी पर दायित्व लगाया गया। इन्हें इस सामान्य आदेश द्वारा निपटाया जा रहा है। इस अपील में पक्षकारों को दावा ट्रिब्यूनल में उनके वर्णन के अनुसार संदर्भित किया जाएगा।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. श्री रोहिताश्व सिंह, एमएसी संख्या 672/2015 में अपीलकर्ता के वकील, ने प्रस्तुत किया कि विवादित अवार्ड पारित करते समय दावा ट्रिब्यूनल ने बीमा कंपनी पर दायित्व लगाने में अवैधता की है। उनके अनुसार, प्रश्नगत वाहन को मृतक द्वारा चलाया जा रहा था, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (जिसे '1988 का अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 134 के खंड (c) के तहत आवश्यक जानकारी प्रश्नगत वाहन के मालिक द्वारा प्रदान नहीं की गई थी। इसलिए, अपीलकर्ता/बीमा कंपनी पर कोई दायित्व नहीं लगाया जा सकता है। समर्थन में, उन्होंने इस न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा दिए गए निर्णय, **द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम श्रीकांत सिंह और अन्य**, एमएसी संख्या 1040/2008, दिनांक 13.10.2011, पर अपना

अवलंब जताया।

3. दूसरी ओर, श्री ए. एल. सिंगरौल, एमएसी संख्या **369/2016** में अपीलकर्ता/दावेदार के वकील, ने विवादित अवार्ड का समर्थन करते हुए प्रस्तुत किया कि दावा ट्रिब्यूनल ने मृतक की आय का आधा हिस्सा कटौती करने के बजाय एक तिहाई कटौती करने में त्रुटि की है, जो **1988** के अधिनियम की धारा **163-A** के तहत दूसरी अनुसूची में निर्धारित प्रावधान के विपरीत है, और इस प्रकार दावेदार को कम मुआवजा दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. मैंने पक्षकारों के वकीलों की दलीलें सुनी हैं और संपूर्ण अभिलेख का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है।

5. 1988 के अधिनियम की धारा 163-A के तहत दावा मृतक उमेश सिंह ठाकुर खंगार की विधवा द्वारा 24.01.2010 को हुई दुर्घटना के संबंध में किया गया है। दावा याचिका के अनुसार, मृतक उमेश सिंह ठाकुर प्रश्नगत वाहन 'पिक-अप वैन' जिसका पंजीकरण संख्या सी.जी. 04 जे.बी. 5524 था, को चला रहे थे, जो गैर-आवेदक संख्या 1., राजेश्वर सिंह खंगार के स्वामित्व में था और गैर-आवेदक संख्या 2/फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ बीमित था। सुसंगत समय पर, मृतक राजिम जा रहे थे और जैसे ही वे गटापारा नहर के निकट पहुंचे, उन्होंने अपना नियंत्रण खो दिया, जिसके परिणामस्वरूप वे बुरी तरह घायल हो गए और अस्पताल में भर्ती कराए गए और उपचार

के दौरान 16.02.2010 को उनकी मृत्यु हो गई। दावा याचिका में यह तर्क दिया गया है कि मृतक पेशे से एक चालक थे और प्रतिदिन 200/- रुपये के दैनिक भत्ते के अलावा 3,200/- रुपये प्रति माह कमाते थे, और इस प्रकार कुल मुआवजे की राशि 15,50,000/- रुपये दावा की गई है।

6. उपरोक्त दावे को गैर-आवेदक संख्या **1**/वाहन के मालिक द्वारा इस आधार पर विवादस्पद किया गया है कि उनका वाहन गैर-आवेदक संख्या **2**/बीमा कंपनी के साथ बीमित था, इसलिए यदि दायित्व लगाया जाता है, तो उसकी क्षतिपूर्ति बीमा कंपनी द्वारा की जा सकती है। जबकि गैर-आवेदक संख्या **2**/बीमा कंपनी ने दावे को मुख्य रूप से इस आधार पर विवादस्पद किया है कि प्रश्नगत वाहन को मृतक द्वारा चलाया जा रहा था, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और **1988** के अधिनियम की धारा 134 के खंड **(c)** के तहत आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं की गई थी। इसलिए, इस सांविधिक प्रावधान के उल्लंघन के कारण, बीमा कंपनी को दायित्व नहीं दिया जा सकता है। यह आगे इस आधार पर विवादस्पद किया गया है कि मृतक एक तीसरा पक्ष नहीं था क्योंकि वह स्वयं प्रश्नगत वाहन चला रहा था, इसलिए दावा याचिका प्रचलन योग्य नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करने के बाद, दावा ट्रिब्यूनल ने यह निर्धारित किया है कि **24.01.2010** को हुई दुर्घटना में मृतक उमेश सिंह ठाकुर, जो प्रश्नगत वाहन के चालक थे, बुरी तरह घायल हो गए और उपचार के दौरान **16.02.2010** को उनकी मृत्यु हो गई।

ट्रिब्यूनल ने यह भी निर्धारित किया कि प्रश्नगत वाहन के चालक के पास प्रभावी और वैध ड्राइविंग लाइसेंस था और बीमाकर्ता यह साबित करने में विफल रहा कि वाहन का उपयोग बीमा पॉलिसी के उल्लंघन में किया गया था। परिणामस्वरूप, बीमा कंपनी पर दायित्व लगाते हुए और मृतक की आय 3,200/- रुपये प्रति माह, वार्षिक 38,400/- रुपये आंकते हुए, उसमें से आधी राशि उनके व्यक्तिगत खर्च के लिए काटकर और 18 के गुणांक को लागू करते हुए, कुल मुआवजे की राशि 3,62,600/- रुपये दावा याचिका दाखिल करने की तारीख से इसके वसूली तक 6% वार्षिक ब्याज के साथ दी गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. असंतुष्ट होकर, बीमाकर्ता और दावेदार दोनों ने ये अपीलें दायर की हैं। MAC संख्या 672/2015 में, बीमा कंपनी द्वारा दायर अपील में, अपीलकर्ता के वकील ने यह तर्क दिया है कि 1988 के अधिनियम की धारा 134 के तहत आवश्यक ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी प्रदान नहीं करने के कारण, यह नहीं माना जा सकता है कि मृतक, जो प्रश्नगत वाहन चला रहा था, के पास ड्राइविंग लाइसेंस था।

9. अपीलकर्ता के उपरोक्त तर्क पर विचार करने के लिए, मैंने संपूर्ण रिकॉर्ड की जांच की और इसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि न तो मृतक/प्रश्नगत वाहन के चालक का ड्राइविंग लाइसेंस जब्त किया गया था और न ही 1988 के अधिनियम की धारा 134 के खंड (c) के उप-खंड (iv) के तहत आवश्यक जानकारी मालिक द्वारा प्रदान की गई थी।

इस प्रकार, यह प्रतीत होता है कि प्रारंभिक भार वाहन के मालिक द्वारा उक्त प्रावधान के अनुसार नहीं उठाया गया था। यह प्रावधान सुसंगत है और इसे यहां निम्नानुसार उद्धृत किया गया है:

> **134. दुर्घटना और व्यक्ति को चोट लगने की स्थिति में चालक का कर्तव्य।**
>
> जब किसी व्यक्ति को चोट लगती है या किसी तीसरे पक्ष की संपत्ति को नुकसान होता है, जो किसी दुर्घटना के परिणामस्वरूप होता है जिसमें एक मोटर वाहन शामिल होता है, तो वाहन का चालक या वाहन का प्रभारी व्यक्ति:
>
> (a) जब तक कि भीड़ की हिंसा या उसके नियंत्रण से बाहर किसी अन्य कारण के कारण ऐसा करना संभव न हो, चोटिल व्यक्ति को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए सभी उचित कदम उठाएगा, जिसमें उसे निकटतम चिकित्सक या अस्पताल में ले जाना शामिल है, और यह प्रत्येक पंजीकृत चिकित्सक या अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर का कर्तव्य होगा कि वह चोटिल व्यक्ति की तुरंत देखभाल करे और चिकित्सा सहायता या उपचार प्रदान करे, बिना किसी प्रक्रियात्मक औपचारिकता की प्रतीक्षा किए, जब तक कि चोटिल व्यक्ति या उसका अभिभावक, यदि वह नाबालिग है, अन्यथा इच्छा न करे;

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(b) पुलिस अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर उसे आवश्यक जानकारी प्रदान करेगा, या यदि कोई पुलिस अधिकारी मौजूद नहीं है, तो घटना की परिस्थितियों की रिपोर्ट निकटतम पुलिस स्टेशन में जितनी जल्दी संभव हो, और किसी भी स्थिति में घटना के 24 घंटे के भीतर करेगा;

(c) बीमाकर्ता को, जिसने बीमा प्रमाणपत्र जारी किया है, दुर्घटना की घटना के बारे में लिखित रूप में निम्नलिखित जानकारी प्रदान करेगा:

(i) बीमा पॉलिसी संख्या और इसकी वैधता की अवधि;

(ii) दुर्घटना की तारीख, समय और स्थान;

(iii) दुर्घटना में घायल या मारे गए व्यक्तियों का विवरण;

(iv) चालक का नाम और उसके ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण।

स्पष्टीकरण: इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "चालक" शब्द में वाहन का मालिक भी शामिल है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. उपरोक्त प्रावधान, विशेष रूप से खंड (c) के उप-खंड (iv) के सरसरी अवलोकन से यह स्पष्ट है कि चालक पर, जिसमें इस प्रावधान के स्पष्टीकरण के आधार पर मालिक भी शामिल है, बीमाकर्ता को ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण प्रदान करने का कर्तव्य है। इस मामले में, न तो ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत किया गया था और न ही इसका विवरण प्रश्नगत वाहन के मालिक द्वारा प्रदान किया गया था। इसे प्रदान नहीं

करने से 1988 के अधिनियम के सांविधिक प्रावधानों का उल्लंघन होगा और ऐसी परिस्थितियों में बीमा कंपनी को दायित्व नहीं दिया जा सकता है।

11. इस मोड़ पर, श्री सिंह द्वारा प्रस्तुत **द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड** (उपरोक्त) के मामले में निर्धारित सिद्धांतों पर विचार करना है, जहां प्रश्नगत वाहन के चालक ने 1988 के अधिनियम की धारा 134 के खंड (c) के उप-खंड (iv) के तहत आवश्यकता को पूरा करने में विफल रहा था। उस तथ्यात्मक परिदृश्य में, इस प्रावधान की व्याख्या करते हुए, पैराग्राफ 7 में यह निर्धारित किया गया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

07) 1988 के अधिनियम की धारा 134 में प्रावधान है कि चालक का कर्तव्य है कि वह बीमाकर्ता को, जिसने बीमा प्रमाणपत्र जारी किया है, दुर्घटना की घटना के बारे में लिखित रूप में निम्नलिखित जानकारी प्रदान करे:

(i) बीमा पॉलिसी संख्या और इसकी वैधता की अवधि;

(ii) दुर्घटना की तारीख, समय और स्थान;

(iii) दुर्घटना में घायल या मारे गए व्यक्तियों का विवरण;

(iv) चालक का नाम और उसके ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण।

इसके अलावा, स्पष्टीकरण में यह स्पष्ट किया गया है कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "चालक" शब्द में वाहन का मालिक भी शामिल है। इसलिए, धारा 134 के खंड (c) के उप-खंड (iv) वाहन के मालिक और चालक पर चालक और उसके ड्राइविंग लाइसेंस का

विवरण प्रकट करने का कर्तव्य लगाता है। इस प्रकार, यदि मालिक या चालक द्वारा विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो 1988 के अधिनियम के सांविधिक प्रावधानों का उल्लंघन होता है और इसके लिए बीमा कंपनी को दायित्व नहीं दिया जा सकता है।

12. उपरोक्त सिद्धांतों को इस मामले पर लागू करते हुए और विशेष रूप से जब प्रश्नगत वाहन के मालिक द्वारा मृतक/चालक के ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण प्रदान करने में उक्त सांविधिक प्रावधान का पालन नहीं किया गया है, तो यह मानना कठिन है कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. फिर भी, **पप्पू और अन्य बनाम विनोद कुमार लांबा और अन्य,** AIR 2018 SC 592 के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि बीमा कंपनी पर बोझ तभी स्थानांतरित होगा जब प्रश्नगत वाहन का मालिक यह प्रमाणित करे कि उसे यह ज्ञात था कि प्रश्नगत वाहन का चालक उसके द्वारा अधिकृत था और उसके पास सुसंगत समय पर वैध ड्राइविंग लाइसेंस था। इसका पैराग्राफ 11 सुसंगत है और इसे यहां निम्नानुसार उद्धृत किया गया है:

प्रश्न यह है: क्या यह तथ्य कि प्रश्नगत वाहन DIL-5955 प्रतिवादी संख्या 2 बीमा कंपनी द्वारा बीमित था, स्वतः ही बीमा कंपनी को दायित्व में डाल देगा? इस न्यायालय ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (AIR 2004 SC 1531) (उपरोक्त) के मामले में, 1988 के मोटर वाहन अधिनियम की धारा 149(2)(a)(ii) के तहत बीमा कंपनी के लिए

उपलब्ध बचावों पर ध्यान दिया है। बीमा कंपनी यह बचाव लेने की हकदार है कि प्रश्नगत वाहन को एक अनधिकृत व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था या वाहन चलाने वाले व्यक्ति के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। बीमा कंपनी पर भार तभी स्थानांतरित होगा जब प्रश्नगत वाहन का मालिक यह प्रमाणित करे कि उसे यह ज्ञात था कि प्रश्नगत वाहन का चालक उसके द्वारा अधिकृत था और उसके पास प्रासंगिक समय पर वैध ड्राइविंग लाइसेंस था। इस मामले में, प्रतिवादी संख्या 1, प्रश्नगत वाहन के मालिक ने केवल यह अस्पष्ट तर्क दिया कि प्रश्नगत वाहन DIL-5955 को एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस धारक व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था। उन्होंने चालक का नाम और उसके अन्य विवरण प्रकट नहीं किए। इसके अलावा, प्रतिवादी संख्या 1 ने साक्ष्य बॉक्स में प्रवेश नहीं किया या इस तर्क के समर्थन में किसी गवाह की जांच नहीं की। प्रतिवादी संख्या 2 बीमा कंपनी ने लिखित बयान में इस तर्क का स्पष्ट रूप से खंडन किया और यह भी दावा किया कि प्रश्नगत वाहन को एक अनधिकृत व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था और उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। प्रतिवादी संख्या 1, प्रश्नगत वाहन के मालिक ने जोगिंदर सिंह का एक ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत किया, बिना यह स्पष्ट किए कि वही जोगिंदर सिंह वास्तव में प्रासंगिक समय पर प्रश्नगत वाहन चलाने के लिए अधिकृत था। केवल तभी बोझ स्थानांतरित होगा, जिससे बीमा कंपनी को ऐसे साक्ष्य का खंडन करने और अपने बचाव को साबित करने के लिए अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। केवल प्रश्नगत ट्रक

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

के संबंध में एक वैध बीमा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना प्रतिवादी संख्या 1 के लिए पर्याप्त नहीं था कि वह बीमा कंपनी को अपने वाहन के चालक की लापरवाह और लापरवाह ड्राइविंग से उत्पन्न दायित्व को निर्वहन करने के लिए दायित्व में डाले। बीमा कंपनी को एक वैध बीमा पॉलिसी के आधार पर दायित्व में तभी डाला जा सकता है जब प्रश्नगत वाहन के मालिक द्वारा मूल तथ्यों को प्रस्तुत और साबित किया जाए – कि वाहन न केवल बीमित था बल्कि यह एक अधिकृत व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था जिसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस था। लिखित बयान में चालक का नाम प्रकट किए बिना या यह साबित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत किए बिना कि प्रस्तुत ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति वास्तव में उस व्यक्ति की थी जो प्रासंगिक समय पर प्रश्नगत वाहन चलाने के लिए अधिकृत था, वाहन का मालिक अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकता है। बीमा कंपनी तभी दायित्व में आएगी जब ऐसे मूलभूत तथ्यों को प्रश्नगत वाहन के मालिक द्वारा प्रस्तुत और साबित किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. इस प्रकार, उपरोक्त सिद्धांतों के आधार पर यह स्पष्ट है कि चालक के ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में मालिक के ज्ञान में मूल तथ्यों को न केवल प्रस्तुत करना आवश्यक था बल्कि उन्हें साबित भी करना था और तभी भार बीमा कंपनी पर स्थानांतरित होगा। हालांकि, मालिक द्वारा दायर लिखित बयान के सरसरी अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस के विवरण के संबंध में कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया है

और न ही इसका कोई विवरण अपने बयान में प्रस्तुत किया है। ड्राइविंग लाइसेंस के किसी भी विवरण के अभाव में, इसलिए, बीमाकर्ता से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वह यह साबित करे कि प्रश्नगत वाहन का चालक प्रभावी और वैध ड्राइविंग लाइसेंस धारक था या नहीं। ऐसी स्थिति में, यह नहीं माना जा सकता है कि प्रश्नगत वाहन को चालक/मृतक द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस के साथ चलाया जा रहा था।

15. परिणामस्वरूप, यह निर्धारित किया गया है कि प्रश्नगत वाहन को मृतक द्वारा चलाया जा रहा था, जिसके पास प्रासंगिक समय पर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और इस प्रकार **24.01.2010** को हुई दुर्घटना के संबंध में **1988** के अधिनियम के सांविधिक प्रावधानों के उल्लंघन के कारण बीमा कंपनी को दायित्व में नहीं डाला जा सकता है। परिणामस्वरूप, दावा ट्रिब्यूनल द्वारा बीमा कंपनी पर दायित्व लगाने का निर्णय रद्द कर दिया गया है और बीमा कंपनी को इसके दायित्व से मुक्त किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. जहां तक दावा ट्रिब्यूनल द्वारा मृतक की आय का आधा हिस्सा कटौती करने के बजाय एक तिहाई कटौती करने और **1988** के अधिनियम की धारा **163-A** के तहत दूसरी अनुसूची के विपरीत और संपत्ति के नुकसान पर विचार नहीं करने के संबंध में दिए गए मुआवजे की राशि का संबंध है, इसे संशोधित किया जाना चाहिए। परिणामस्वरूप, दावा ट्रिब्यूनल द्वारा मृतक की आय **3,200/-** रुपये प्रति माह, वार्षिक **38,400/-** रुपये आंकते हुए और **18** के गुणांक को लागू करते हुए, यह **6,91,200/-** रुपये होगा और इसमें से एक तिहाई, यानी **2,30,400/-**

रुपये, मृतक के व्यक्तिगत खर्च के लिए काटकर, कुल निर्भरता **4,60,800/-** रुपये **(6,91,200 – 2,30,400)** होगी। इसके अतिरिक्त, दावेदार को पारंपरिक मदों के लिए **9,500/-** रुपये की राशि का हकदार होगा, जबकि दावा ट्रिब्यूनल ने संपत्ति के नुकसान पर विचार नहीं करते हुए **7,000/-** रुपये दिए थे। इस प्रकार, दावेदार को कुल मुआवजे की राशि **4,70,300/-** रुपये का हकदार है और बढ़ी हुई राशि **1,07,700/-** रुपये **(4,70,300 – 3,62,600)** दावा याचिका दाखिल करने की तारीख से इसके वसूली तक **6%** वार्षिक ब्याज के साथ दी जाएगी। दावेदार द्वारा दायर MAC संख्या **369/2016** की अपील को इस प्रकार स्वीकार किया जाता है और विवादित को उपरोक्त संशोधनों के साथ संशोधित किया जाता है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. इस स्तर पर, श्री सिंगरौल, अपीलकर्ता/दावेदार के वकील ने प्रस्तुत किया कि हालांकि बीमा कंपनी को दायित्व से मुक्त कर दिया गया है, लेकिन दुर्घटना में उसकी भागीदारी पाई गई है, इसलिए बीमा कंपनी को दावेदार को अवार्ड राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाए और इसे बीमित (गैर-आवेदक संख्या **1**) से वसूल करने का अधिकार दिया जाए, मैनेजर, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम साजू पी. पॉल और अन्य, **(2013) 2** SCC **41**, और मनुआरा खातून और अन्य बनाम राजेश कुमार सिंह और अन्य, **(2017) 4** SCC **796** में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर।

18. उपरोक्त तर्क और सिद्धांतों पर विचार करते हुए, यह उचित होगा कि गैर-आवेदक संख्या **2**/बीमा कंपनी को पहले दावेदार को अवार्ड राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाए और फिर इसे प्रश्नगत वाहन के मालिक, यानी गैर-आवेदक संख्या **1** से वसूल करने का अधिकार दिया जाए। तदनुसार, मैं गैर-आवेदक संख्या **2**/फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को पहले दावेदार को उपरोक्त अवार्ड राशि का भुगतान करने और फिर इसे प्रश्नगत वाहन के मालिक, यानी गैर-आवेदक संख्या **1**/राजेश्वर सिंह राजपूत खंगार से इसी मामले में उत्पन्न निष्पादन कार्यवाही में वसूल करने का निर्देश देता हूं।

19. परिणामस्वरूप, दोनों अपीलें उपरोक्त टिप्पणियों के साथ स्वीकार की जाती हैं। दावा ट्रिब्यूनल द्वारा निर्धारित शेष शर्तें यथावत रहेंगी। खर्चों के संबंध में कोई आदेश नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Sd/-

(संजय अग्रवाल)
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**